कुपोषण मुक्त भारत के लिए

लेखक- शोभा सूरी (सीनियर फेलो, हेल्थ इनिशिएटिव, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था, स्वास्थ्य) से संबंधित है।

द हिन्दू

30 अप्रैल, 2019

"देश को 2022 तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन की आवश्यकता है।"

इस चुनावी मौसम में न केवल मतदाताओं से किये गये वादे, बल्कि बच्चों के जीवन, राष्ट्र के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए किए गए वादों को भी निभाना महत्वपूर्ण है। 1975 से विभिन्न कार्यक्रमों,जैसे कि समेकित बाल विकास सेवाओं का सृजन और मध्याह्न भोजन योजना का राष्ट्रीय कवरेज को लागू करने के बावजूद भारत निरंतर उच्च दर के कुपोषण से जूझ रहा है। पोषण में सुधार और स्टंटिंग (उम्र के अनुसार बच्चों का कद नहीं बढ़ना) को प्रबंधित करना बड़ी चुनौतियां हैं और उन्हें केवल एक अंतर-क्षेत्रीय रणनीति के साथ संबोधित किया जा सकता है।

स्टंटिंग का मानव पूंजी, गरीबी और इक्विटी पर आजीवन प्रभाव रहता है। यह शिक्षा और कम पेशेवर अवसरों पर भी असर डालता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) -4 के अनुसार, वर्षों से सीमांत सुधार के बावजूद, भारत में स्टंटिंग का उच्च स्तर है। 2015-16 में, पाँच साल से कम उम्र के 38.4% बच्चे स्टंटिंग से ग्रसित थे और 35.8% बच्चों में कम वजन की समस्या थी। भारत मानव पूंजी सूचकांक पर 195 देशों में से 158वीं रैंक पर है।

स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश की कमी के कारण आर्थिक विकास धीमा हो गया है। विश्व बैंक के अनुसार, 'बचपन में स्टंटिंग के कारण वयस्क ऊंचाई में 1% की हानि आर्थिक उत्पादकता में 1.4% की हानि के साथ जुड़ी हुई है।' स्टंटिंग का भविष्य की पीढ़ियों पर भी प्रभाव पड़ता है। चूंकि 2015-16 में 53.1% महिलाएं रक्तहीनता या एनीमिया से पीड़ित थीं, इसलिए भविष्य में उनके गर्भधारण और उनके बच्चों पर इसका स्थायी प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब शिशुओं को अपर्याप्त आहार खिलाया जाता है।

महत्वाकांक्षी लक्ष्य

2017 की राष्ट्रीय पोषण रणनीति का उद्देश्य 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त देश बनाना है। योजना यह है कि एनएफएचएस -4 के स्तरों से 2022 तक प्रति वर्ष लगभग तीन प्रतिशत बच्चों(0-3 वर्ष) में स्टंटिंग की समस्या को कम करना है और बच्चों,किशोर तथा प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया की समस्या को एक तिहाई तक कम करना है।

यह एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, क्योंकि अगर आंकड़ों पर गौर करें, तो हम पाएंगे कि स्टंटिंग की समस्या में गिरावट पिछले 10 वर्षों में प्रति वर्ष केवल एक प्रतिशत की हुई है अर्थात् यह 2006 में 48% थी और 2016 में 38.4% तक रही। अब समय आ गया है कि इन मामलों से जुड़े मंत्रालयों द्वारा गंभीर संरेखण, पोषण कार्यक्रमों के अभिसरण और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी निगरानी पर ध्यान दिया जाये।

स्टंटिंग पर उपलब्ध डेटा हमें बताता है कि भविष्य के कार्यक्रमों को कहाँ केंद्रित करना है। स्टंटिंग की समस्या उम्र के साथ बढ़ती चली जाती है और 18-23 महीनों में अपने चरम पर पहुँच जाती है। स्तनपान, उम्र-उपयुक्त पूरक आहार, पूर्ण टीकाकरण और विटामिन-एकी खुराक को समय पर बच्चों को देने से परिणाम में काफी सुधार आते हैं। हालांकि, आंकड़े बताते हैं कि जन्म के एक घंटे के भीतर केवल 41.6% बच्चों को स्तनपान कराया जाता है, 54.9% को विशेष रूप से छह महीने के लिए स्तनपान

कराया जाता है, 42.7% को समय पर पूरक आहार प्रदान किया जाता है और दो साल से कम उम्र के केवल 9.6% बच्चों को पर्याप्त आहार प्राप्त होता है।

भारत को इन क्षेत्रों में सुधार करना होगा। विटामिन-ए की कमी से खसरा और डायरिया जैसी बीमारियों का संक्रमण बढ़ सकता है। लगभग 40% बच्चों को पूर्ण टीकाकरण और विटामिन-ए की खुराक नहीं मिल पाती है। इन रोगों की रोकथाम के लिए उन्हें सुविधाएं ये उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

राज्यों और जिलों में बदलाव

एनएफएचएस -4 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की संख्या अधिक है, संभवत: ऐसी स्थिति उन क्षेत्रों में परिवारों की कम सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण है। स्टंटिंग की समस्या लगभग 12 या उससे अधिक वर्षों तक स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाली माताओं की तुलना में बिना स्कूली शिक्षा प्राप्त माताओं से पैदा होने वाले बच्चों में अधिक पायी जाती है। स्टंटिंग घरेलू आय में वृद्धि के साथ लगातार गिरावट को दर्शाती है।

भौगोलिक क्षेत्रों के संदर्भ में, बिहार (48%), उत्तर प्रदेश (46%) और झारखंड (45%) में स्टंटिंग की समस्या की बहुत अधिक दर है, जबकि सबसे कम दरों वाले राज्यों में केरल और गोवा (20%) शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है (पिछले दशक में 15 प्रतिशत की गिरावट)। इस प्रकार, सरकार छत्तीसगढ़ से सबक ले सकती है। हालांकि, तमिलनाडु में सबसे कम प्रगति हुई है।

इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन से पता चलता है कि स्टंटिंग की समस्या जिला स्तर पर (12.4-65.1%) अलग-अलग है और लगभग 40% जिलों में स्टंटिंग का स्तर 40% से ऊपर है। उत्तर प्रदेश सूची में सबसे ऊपर है जहाँ 10 में से छह जिलों में स्टंटिंग की उच्चतम दर है।

इस डेटा को देखते हुए गर्भावस्था से ही स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों के अभिसरण पर कार्य करना चाहिए जब तक कि बच्चा पाँच वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाता। इसके अलावा, भारत को सामाजिक-व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कुपोषण को दूर करने के लिए कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन की वास्तव में आवश्यकता है।

GS World टीम...

वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट-2019

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आइएफपीआरआई) ने वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट-2019 जारी की है।
- रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक आर्थिक विकास बीते साल तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन यह खाद्य संकट की समस्या को कम करने में मद्दगार साबित नहीं हुआ।
- रिपोर्ट के अनुसार भूख और कुपोषण, गरीबी, सीमित आर्थिक अवसर तथा पर्यावरण क्षरण के कारण विश्व के कई हिस्सों में ग्रामीण क्षेत्र संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं।

मुख्य बिंदु

- रिपोर्ट के मुताबिक, विश्व की कुल आबादी में 45.3 प्रतिशत ग्रामीण आबादी है और विश्व की कम-से-कम 70 प्रतिशत आबादी बहुत ही गरीब है।
- विश्व भर में साल 2012 से साल 2017 के बीच कुपोषण के कारण बच्चों के कद न बढ़ने के मामलों में नौ प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी लेकिन इसके बावजूद ऐसे बच्चों की संख्या 15 करोड़ है, जो बहुत अधिक है।
- बच्चों के कद न बढ़ने के मामले और पोषण के अन्य संकेतकों से पता चलता है कि सतत् विकास लक्ष्य की पूर्ति का रास्ता बेहद दुर्गम है।

ग्रामीण स्तर पर

- ग्रामीण आबादी तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर, अपर्याप्त रोजगार और उद्यम निर्माण, खराब बुनियादी ढाँचा तथा अपर्याप्त वित्तीय सेवाओं के कारण पीड़ित है।
- कई देशों में 60 प्रतिशत खेती उन महिलाओं द्वारा की जाती

है जिनके पास संपत्ति या राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होती है या जिनकी कृषि विस्तार सेवाओं तक पहुँच नहीं है।

- विश्व भर में लगभग 50 प्रतिशत ग्रामीण युवाओं के पास कोई औपचारिक रोजगार नहीं है, वे या तो बेरोजगार हैं या अस्थायी रोजगार में लगे हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, नव-प्रवर्तनशील और समग्र पुनरुद्धार के बिना नए अवसरों का लाभ उठाने और बढ़ती चुनौतियों का सामना करने हेतु साल 2030 तक सभी के लिये खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना मुश्किल होगा।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बदलते उपभोग पैटर्न ने शहरीकरण, जनसांख्यिकीय बदलाव, आय में वृद्धि और खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं तथा खाद्य प्रणालियों के बढ़ते एकीकरण से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता और रोजगार के नए अवसर प्रदान किये हैं।

IFPRI के बारे में

- अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI) विकासशील देशों में गरीबी, भूखमरी और कुपोषण को कम करने के लिये अनुसंधान आधारित नीतिगत समाधान प्रदान करता है।
- 1975 में स्थापित IFPRI में वर्तमान में 50 से अधिक देशों में काम करने वाले 600 से अधिक कर्मचारी हैं।
- यह अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान के लिए सलाहकार समूह अर्थात् CGIAR (Consultative Group for International Agricultural Research) का एक अनुसंधान केंद्र है।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स-2018

संदर्भ

- पिछले वर्ष ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट-2018 जारी की गई थी।
- रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब भी काफी भुखमरी मौजूद है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स-2018 में कुल 119 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत 103वें पायदान पर है।
- भारत, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों से पीछे है, लेकिन पाकिस्तान से आगे है।
- पाकिस्तान इस रिपोर्ट में 106वें स्थान पर मौजूद है जबकि भारत पिछले वर्ष 100वें स्थान पर था। रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 68 मिलियन लोग रिफ्यूजी कैंप में रहने को मजबूर हैं।

क्या है?

- ग्लोबल हंगर इंडेक्स में विश्व के विभिन्न देशों में खान पान की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा दिया जाता है।
- इसमें यह देखा जाता है कि लोगों को किस तरह का खाद्य पदार्थ मिल रहा है, उसकी गुणवत्ता और मात्रा कितनी है और उसमें कमियां क्या हैं।
- प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में यह रिपोर्ट जारी की जाती है।
- ग्लोबल हंगर इंडेक्स की शुरुआत वर्ष 2006 में इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की थी।
- वेल्ट हंगरलाइफ नाम की एक जर्मन संस्था ने 2006 में पहली बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया था।
- 2018 में इस रिपोर्ट का 13वां एडिशन था।

पिछले वर्षों में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत

- वर्ष 2014 के बाद से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में लगातार गिरावट आई है।
- वर्ष 2014 में भारत जहाँ 55वें पायदान पर था, तो वहीं 2015 में 80वें, 2016 में 97वें और पिछले साल 100वें पायदान पर आ गया।
- वर्ष 2018 की रैंकिंग में भारत पिछले वर्ष की तुलना में तीन पायदान और गिरकर 103वें स्थान पर आ गया है।

प्रमुख तथ्य

- इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी दर्ज की गई है।
- वर्ष 1999-2001 में कुपोषित बच्चों की संख्या 17.6% थी, जबकि वर्ष 2015-17 में यह कम होकर 12.3% पर पहुँच गयी है।
- 1999-2001 में बच्चों की ग्रोथ का आंकड़ा 37.1% था, जबकि 2013-17 में यह कम होकर 27.9% पर पहुँच गया।
- ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बेलारूस टॉप पर है जबकि चीन 25वें, बांग्लादेश 86वें, नेपाल 72वें, श्रीलंका 67वें और म्यांमार 68वें स्थान पर है।
- वर्ष 2018 के सूचकांक के अनुसार जिम्बाब्वे तथा सोमालिया में कुपोषण दर सबसे अधिक 46.6 से 61.8% है।
- बच्चों की वृद्धि दर सबसे कम तिमोर-लेस्ते,इरीट्रिया तथा बुरुंडी में दर्ज की गई है।
- भूख के कारण चाड, हैती, मेडागास्कर, सिएरा लिओन, यमन तथा जाम्बिया में हिंसक हालात बताए गये हैं।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. राष्ट्रीय पोषण मिशन को भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप में जारी किया गया है।
2. अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट (2018) के अनुसार भारत की रैंकिंग 100वीं है।
3. राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य कुपोषण और जन्म के समय बच्चों का वजन कम होने संबंधी समस्याओं को प्रत्येक वर्ष 2% तक कम करना है।
4. राष्ट्रीय पोषण मिशन के अन्तर्गत स्टंटिंग (उम्र की तुलना में लम्बाई का कम बढ़ना) की समस्या को 2022 तक 38.4% से 25% तक करना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) 1 और 2
(b) केवल 2
(c) 1, 3 और 4
(d) 2, 3 और 4

1. Consider the following statements-

1. National Nutrition Mission is propagated jointly by the Ministry of Women and Child Development, Ministry of Health and family Welfare and NITI Aayog of the Government of India.
2. India is ranked 100th according to the Global Hunger Index report, 2018 released by International Food Policy Research Institute.
3. The objective of the National Nutrition Mission is 2% reduction each year in the malnutrition and the problems related to low weight at the time of birth.
4. Under National Nutrition Mission, the stunting is to be reduced to 25% from 38.4%.

Which of the above statements is/are correct?

(a) 1 and 2
(b) Only 2
(c) 1, 3 and 4
(d) 2, 3 and 4

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न:- भारत जैसे विकासशील देश में कुपोषण की समस्या बेहद गंभीर बनती जा रही है। क्या सामाजिक-आर्थिक असमानता और कुपोषण एक-दूसरे से अन्तर्संबंधित हैं? टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द)

Q. The problem of malnutrition is becoming a serious problem for the developing countries like India. Are socio-economic inequality and maluntrition mutually interrelated? Comment. (250 Words)

प्रश्न:- भारत में कुपोषण के बढ़ते प्रभावों का मूल्यांकन करते हुए कुपोषण की समस्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा चलाये गए कार्यक्रम राष्ट्रीय पोषण मिशन की समीक्षा कीजिए। (250 शब्द)

Q. Evaluating the increasing effects of malnutrition in India, review the National Nutrition Mission Started by the government to tackle the problem of malnutrition. (250 Words)

नोट : 29 अप्रैल को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a) होगा।